अलका शर्मा भारत का संघ और अन्य का संघ

(सुदीप अहलूवालिया, जे.)

सूर्यकांत और सुदीप अहलूवालिया जे.जे. के समक्ष

अलका शर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

2014 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16530

21 फ़रवरी 2017

ए. प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम, 1985-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश VII, नियम.3, 4 और 5-दलीलें-न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही का निर्णय लेने के उद्देश्य से, सी. पी. सी. के उक्त नियम जो दलीलों को नियंत्रित करते हैं, पूरी तरह से लागू होते हैं-लिखित बयान में ओ. ए. के प्रत्येक आरोप का खंडन शामिल होना चाहिए-लिखित बयान विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए-यदि इनकार टालमटोल या गैर-विशिष्ट है तो शिकायत में आरोप को स्वीकार किया जाएगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, मूल आवेदन में किए गए विशिष्ट आरोपों का संज्ञान नहीं लेने में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण, बाद के लिखित परीक्षा नोटिस के गैर-संचार के संबंध में, साथ ही कर्मचारी द्वारा वर्ष 2000 में पहली बार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित साक्षात्कार आयोजित या संचार नहीं करने के बारे में, जब इन विशिष्ट आरोपों को वस्तुतः अस्वीकृत छोड़ दिया गया था, निश्चित रूप से याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है।निर्विवाद रूप से, न्यायाधिकरण में न्यायिक कार्यवाही तय करने के उद्देश्य से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित अभिवचनों को नियंत्रित करने वाले नियम पूरी तरह से लागू होते हैं।आदेश VIII नियम 3,4 और 5 में विशेष रूप से यह अपेक्षा की गई है कि लिखित बयान में, वाद में प्रत्येक आरोप का खंडन (वर्तमान मामले में ओ. ए. के समतुल्य) 'विशिष्ट' और स्पष्ट होना चाहिए और इनकार के टालमटोल या विशिष्ट नहीं होने की स्थिति में, वाद में लगाए गए तथ्य के आरोपों को 'स्वीकार करने के लिए लिया जाएगा।'

(पैरा 5)

बी. रेलवे सेवकों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964-आदेश 75-अआदेशित मृत कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान न देना-आवश्यक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण किया है-साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है-यह दिखाने के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं है कि साक्षात्कार आदेशित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त थी-आयोजित, पत्नी पारिवारिक पेंशन देने की हकदार थी जो सेवाओं के आदेशित नहीं होने के कारण नहीं दी गई थी-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

माना जाता है कि इस प्रकार जो समग्र तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि मृतक कर्मचारी ने 598 से अधिक के लिए काम किया था। 30.07.1992 से लेकर 14.12.2006 पर उनकी मृत्यु तक आवश्यक एक वर्ष की सेवा, और उन्होंने 5.08.1992 पर आवश्यक चिकित्सा परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी।नतीजतन, नौकरी में उनकी मृत्यु के कारण, उनकी विधवा परिवार पेंशन देने की हकदार बन जाएगी।हालाँकि यह अनुमति नहीं दी गई थी, जाहिरा तौर पर क्योंकि उनकी सेवाओं को 'नियमित नहीं किया गया था'।लेकिन जैसा कि याचिकाकर्ता के विशिष्ट कथनों के आलोक में तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से विचार करके और प्रतिवादीओं द्वारा इससे इनकार करके सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नियमितकरण की ऐसी कमी के लिए कर्मचारी स्वयं दोषी नहीं था।उन्होंने वर्ष 2000 में आवश्यक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उस उद्देश्य के लिए

उत्तरदाताओं के अपने स्वयं के लिखित संचार दिनांक 30.06.2000 के बावजूद उन्हें साक्षात्कार के लिए कभी नहीं बुलाया गया।उन्हें अपने नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से वर्ष 2002 और 2004 द्वारा सफल लिखित परीक्षाओं के बारे द्वारा सूचित भी नहीं किया गया था।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित किया कि, उपरोक्त कारणों से, न्यायाधिकरण का विवादित आदेश अस्थिर है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है।इसलिए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे मृतक कर्मचारी की सेवाओं को नियमित मानते हुए परिवार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अनुदान के लिए आवश्यक कार्य करें।हालाँकि, वह एल. डी. में अपना मूल आवेदन दाखिल करने से पहले केवल तीन साल की अवधि के लिए पेंशन की अवशिष्ट राशि की हकदार होगी। न्यायाधिकरण अर्थात मई, 2012 से आगे।

(पैरा 11)

डी.आर.शर्मा, अधिवक्ता,याचिकाकर्ता के लिए.

करमजीत वर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

सुदीप अहलूवालिया, जे।

(1) याचिकाकर्ता दिनांकित 16.9.2013 (अनुलग्नक पी-4) के विवादित आदेश को रद्द करने की मांग करता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ ने उनके मूल आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्देश देने की मांग की थी कि वे अपने दिवंगत पति की सेवाओं को नियमित/स्थायी के रूप में माने, जो कि 30.7.1992 से 14.12.2006 तक प्रभावी है, उनके पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के लिए, और अवशिष्ट, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान सहित उनकी पारिवारिक पेंशन जारी करने के लिए।

(2) उनका मामला यह है कि उनके दिवंगत पति प्रदीप शर्मा ने शुरू में रेलवे आरक्षण कार्यालय, लुधियाना में अस्थायी बुकिंग क्लर्क के रूप में सात महीने तक काम किया था और 4.5.1985 से 12.8.1986 के बीच रुक-रुक कर काम किया था।इसके बाद उन्हें 12 अन्य व्यक्तियों के साथ 30.7.1992 पर अस्थायी आधार पर एक बुकिंग क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया।उन्होंने 5.8.1992 पर इस तरह की नियुक्ति के लिए आवश्यक चिकित्सा परीक्षा को विधिवत उत्तीर्ण किया।1995 में, उनके अनुरोध पर उनका तबादला कर दिया गया था।अगस्त, 1999 में रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे में काम करने वाले मोबाइल बुकिंग क्लर्कों (एम. बी. सी.) को नियमित करने का फैसला किया।उत्तर रेलवे, फिरोजपुर के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पति और 11 अन्य एम. बी. सी. को उस उद्देश्य के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का निर्देश दिया, क्योंकि वह अन्यथा नियमितीकरण के लिए पात्र थे, क्योंकि उन्होंने उस उद्देश्य के लिए 891 कार्य दिवसों से अधिक का वास्तविक काम किया था।उन्होंने 11.3.2000 पर आयोजित लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांकित 30.6.2000 (अनुलग्नक ए-4) पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि उन्हें 11 अन्य लोगों के साथ निकट भविष्य में आयोजित होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।हालाँकि, उन्हें लंबे समय तक इस तरह का कोई साक्षात्कार कॉल नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने साक्षात्कार के संबंध में आवश्यक कार्य करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 को 9.12.2000 (अनुलग्नक ए-5) पर एक पत्र लिखा, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।इसके बाद, याचिकाकर्ता के पति को रेलवे डॉक्टर बीमार-सूची में रहते हुए, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा स्टेशन अधीक्षक, लुधियाना के माध्यम से 22.8.2001 (अनुलग्नक ए-6) दिनांकित पत्र के माध्यम से 15.9.2001 पर लिखित परीक्षा के लिए बख्शा जाना आवश्यक था, लेकिन उन्हें वास्तव में इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था।इसके बाद, एमबीसी की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक और लिखित परीक्षा 26.10.2002 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर से याचिकाकर्ता के पति को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था।इसलिए उन्होंने अपने पत्र (अनुलग्नक ए-7) के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 से अनुरोध किया कि उन्हें स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा का मौका दिया जाए क्योंकि इसमें उपस्थित नहीं होने के लिए उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।उनकी मृत्यु 14.12.2006 पर हुई, लेकिन चार दिन बाद,

प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांकित 18.12.2006 (अनुलग्नक ए-8) का पत्र जारी किया, जिसमें स्टेशन अधीक्षक से उन्हें और सात अन्य लोगों को 6.1.2007 पर होने वाले लिखित परीक्षण के लिए छोड़ने के लिए कहा गया, भले ही वह पहले ही मर चुके थे।

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पति को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होना था और उनकी मृत्यु के समय उन्होंने मोबाइल बुकिंग क्लर्क के रूप में प्रतिवादी/विभाग के साथ 14 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की थी।इसलिए, उन्होंने अपने मूल आवेदन के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रतिवादीओं को अपने पति की सेवाओं को 30.7.1992 से 14.12.2006 600 तक स्थायी मानने का निर्देश देने की मांग की गई थी।और उसके पक्ष में पेंशन लाभ और पारिवारिक पेंशन जारी करने के लिए, इस संबंध में उसके दावे को रेलवे अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.11.2013 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

(4) हालाँकि, न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया -

"13. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मृत कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी आधार पर दिनांक 1 के नोटिस के माध्यम से की गई थी और नोटिस में ही यह स्पष्ट किया गया था कि नियुक्त व्यक्तियों का नियमितकरण 3 साल की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद "चयन का सकारात्मक कार्य" द्वारा प्रभावी होगा।आवेदक के पति को चयन प्रक्रिया को पास करने के लिए तीन अवसर मिले क्योंकि लिखित परीक्षा 2000,2001 और 2002 में निर्धारित की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए।मृतक कर्मचारी ने 2004 में एक बार फिर जांच प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया था और यह 2006 में आयोजित किया गया था, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए घोषित तिथि से ठीक पहले, श्री. प्रदीप कुमार की मृत्यु हो गई।पेंशन उद्देश्यों के लिए योग्यता सेवा के संबंध में रेलवे सेवा (पेंशन) नियम स्पष्ट हैं और अस्थायी कर्मचारियों के मामले में यह कहा गया है कि अस्थायी आधार पर दी गई सेवा को उन कर्मचारियों के संबंध में पूरी तरह से गिना जाएगा जिन्हें बाद में मूल पद पर नियुक्त किया गया है।चूंकि उनकी मृत्यु के समय आवेदक अभी भी अस्थायी क्षमता में काम कर रहा था और उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया था, इसलिए वह पेंशन के लिए अयोग्य था और इसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता था।इसलिए इस ओ. ए. को खारिज कर दिया जाता है।"

(5) जैसा कि ऊपर देखा गया है, विवादित आदेश के हाइलाइट किए गए उद्धरणों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रिब्यूनल अपने अंतिम निर्णय पर आ गया है आधार यह है कि मृत कर्मचारी के पास 2000, 2001 और 2002 में निर्धारित लिखित परीक्षा को पास करने के तीन अवसर थे, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और उसने 2004 में एक बार फिर से स्क्रीनिंग प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया था और यह आयोजित किया गया था। 2006 में लेकिन लिखित परीक्षा की तारीख घोषित होने से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है कि उसके मृत पति ने लिखित योग्यता प्राप्त कर ली है दिनांक 30.6.2000 के पत्र (अनुलग्नक ए-4) के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार 2000 में परीक्षा में कभी भी साक्षात्कार नहीं लिया गया। अन्य कर्मचारियों के साथ, जो लिखित परीक्षा में समान रूप से उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें निकट भविष्य में आयोजित होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पांच महीने बाद 9.12.2000 को अनुबंध ए-5 के माध्यम से साक्षात्कार/जरूरी कार्रवाई करने के उनके अनुरोध का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। किसी भी स्तर पर आगामी. यह भी विशिष्ट आरोप था कि 15.9.2001 और 26.10.2002 को निर्धारित बाद की लिखित परीक्षा में नई उपस्थिति के बारे में कभी भी मृत कर्मचारी को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण उन परीक्षाओं में उपस्थित न होने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे विचार में, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण नहीं है बाद में लिखित की गैर-संचारी के संबंध में मूल आवेदन में लगाए गए विशिष्ट आरोपों का संज्ञान लेते हुए परीक्षण नोटिस, साथ ही कर्मचारी द्वारा पहली बार वर्ष 2000 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित साक्षात्कार आयोजित नहीं करना या संचार नहीं करना, जब ये विशिष्ट आरोप वस्तुतः छोड़ दिए गए थे निर्विवाद रूप से, इससे निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निर्विवाद रूप से, न्यायिक कार्यवाही तय करने के उद्देश्य से ट्रिब्यूनल, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित दलीलों को नियंत्रित करने वाले नियम पूरी तरह से लागू हैं। आदेश VIII नियम 3, 4 और 5 विशेष रूप से आवश्यकता है कि एक लिखित बयान में, वादी में

प्रत्येक आरोप का खंडन (वर्तमान मामले में ओ.ए. के बराबर) करना होगा 'विशिष्ट' और स्पष्ट हों और इनकार के अस्पष्ट या विशिष्ट न होने की स्थिति में, वादपत्र में लगाए गए तथ्य के आरोपों को 'स्वीकार किए जाने के रूप में लिया जाएगा'

(6) अब हम इन तथ्यों पर विशिष्ट अभिवचनों का विज्ञापन कर सकते हैं जैसा कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रासंगिक पैराग्राफ 4 (viii) से (xii) में अपने मूल आवेदन में किया गया है, और प्रतिवादीओं द्वारा उनके लिखित बयान में उनका खंडन, जो नीचे दिए गए हैं -

मूल अनुप्रयोग	लिखित कथन
viii) कि 11.03.2000 पर आयोजित लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप वरिष्ठ डी. पी. ओ. N.Rly, फिरोजपुर ने दिनांकित 30.06.2000 पत्र के माध्यम से सूचित किया कि आवेदक के पति को 11 अन्य लोगों के साथ निकट भविष्य में आयोजित होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह के कार्यालय पत्र की एक प्रति दिनांकित 30.06.2000 के रूप में संलग्न है	viii) कि ओ. ए. के पैरा सं. 4 (viii) की सामग्री अभिलेख का विषय है। आवेदक के पति ने उन कारणों से वाइवा वॉस में भाग नहीं लिया जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया गया था।

संलग्नक ए-4।	
ix) कि कोई साक्षात्कार सूचना प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पति ने वरिष्ठ डी. पी. ओ., N.Rly को दिनांकित 09.12.2000 अनुरोध पत्र के माध्यम से अनुरोध किया। फिरोजपुर को आवश्यक कार्य करने के लिए लेकिन आवेदक के पति को साक्षात्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 09.12.2000 दिनांकित ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्नक ए-5 के रूप में संलग्न है।	ix) कि ओ. ए. के इस उप पैरा की सामग्री को स्वीकार नहीं किया जाता है। यह विशेष रूप से दोहराया जाता है कि संलग्नक ए-5 केवल एक बाद का विचार है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, अगली जांच करने से, उस संबंध में किसी भी दावे को त्याग दिया गया माना जाता है। इसके अलावा, यह बहुत देर से किया गया है और इसका कभी पीछा नहीं किया गया था और अब इसे दबाया नहीं जा सकता है।
x) जब आवेदक का पति 06.08.2001 से रेलवे डॉक्टर की	x) कि ओ. ए. के पैरा सं. 4 (x) की सामग्री को उत्तर देने की

बीमार सूची में था, तो वरिष्ठ डी. पी. ओ., N.Rly, फिरोजपुर ने 220.8.2001 दिनांकित पत्र के माध्यम से स्टेशन अधीक्षक, लुधियाना (एस. एस./एल. डी. एच.) से आवेदक के पति को 15.09.2001 पर होने वाली लिखित परीक्षा के लिए छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आवेदक के पति को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। 22.08.2001 दिनांकित ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्नक ए-6 के रूप में संलग्न है।	आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, मृतक कर्मचारी बीमार छुट्टी पर था, इसलिए उसे 26.10.2002 पर लिखित परीक्षा में बैठने का दूसरा मौका दिया गया था, जो वह ड्यूटी से अनुपस्थिति होने के कारण चूक गया था।
xi) एमबीसी की सेवाओं को नियमित करने के उद्देश्य से फिर से लिखित परीक्षा 26.10.2002 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर से आवेदक के पति को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था।	xi) कि ओ. ए. के इस उप पैरा की सामग्री गलत है और अस्वीकार की गई है। इस संबंध में, प्रतिवादी संलग्नक आर-2 के पैरा की सामग्री संलग्नक आर-थाट का उल्लेख करेंगे जो स्थिति को स्पष्ट करता है। आवेदक स्पष्ट रूप से तथ्यों को छिपाने का दोषी है।
xii) आवेदक के उस पति ने दिनांकित 06.05.2004 पत्र के माध्यम से वरिष्ठ डी. पी. ओ. से अनुरोध किया कि वह उसे जांच/लिखित परीक्षा का मौका दे।	xii) कि ओ. ए. के इस उप-भाग के कथन आवेदक के दिमाग के मुकदमा हैं। अनुरोध बहुत देर से किया गया था। द.

क्योंकि उसमें उपस्थित न होने के लिए उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आवेदक के पति को कोई जवाब नहीं दिया गया था। 06.05.2004 दिनांकित ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्नक ए-7 के रूप में संलग्न है।	परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका था और मृतक कर्मचारी ने 26.10.2002 पर आयोजित लिखित परीक्षा में भाग नहीं लिया था, इसके कारण ऊपर दिए गए हैं।

(7) इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के आरोपों को, विशेष रूप से ऊपर रेखांकित किए गए आरोपों को, वर्ष 2000 में उसके पति द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साक्षात्कार आयोजित नहीं करने के संबंध में, और साथ ही उसे बाद की परीक्षा के लिए परीक्षण के गैर-संचार के बारे में जानबूझकर टाल दिया है, जो विशेष रूप से आरोप लगाए गए थे, जिन्हें प्रतिवादी की ओर से स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ओ. ए. में आरोपों के सार को दरकिनार करते हुए इस विशिष्ट आरोप को बताए बिना कि 2000 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मृतक कर्मचारी को साक्षात्कार के लिए कभी कोई तारीख तय नहीं की गई थी या सूचित नहीं किया गया था, या कि उसके अपने लिखित अनुरोधों के बावजूद बाद के वर्षों में उसे परीक्षा के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था।वास्तव में पैरा 4 (ix) में, प्रतिवादी ने इस हद तक सुझाव दिया है जैसे कि मृतक कर्मचारी ने 'अगली परीक्षा' भी दी थी, जो कि याचिकाकर्ता के विशिष्ट आरोपों के स्पष्ट रूप से विपरीत है।यदि मृतक कर्मचारी ने वास्तव

में कभी कोई 'अगली परीक्षा' दी थी, तो प्रतिवादीओं द्वारा संबंधित विवरण और उसकी तारीख का खुलासा किया जाना चाहिए था।लेकिन ऐसा करने में उनकी सचेत चूक और उनके लिखित बयान में अन्य स्पष्ट रूप से टालमटोल करने वाले इनकार स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि वास्तव में, मूल आवेदन में उनके खिलाफ लगाए गए प्रासंगिक आरोप काफी हद तक सच थे।

(8) इस मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि एल. डी. न्यायाधिकरण ने 2000,2001 और 2002 में निर्धारित लिखित परीक्षा में 'मृत कर्मचारी ने या तो साक्षात्कार से खुद को अनुपस्थित रखा था' या 'सफल नहीं हुआ था' के बारे में प्रतिवादीओं की दलीलों को यांत्रिक रूप से स्वीकार करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि एल. डी. न्यायाधिकरण ने शायद मूल आवेदन में किए गए विशिष्ट अभिवचनों के आलोक में तथ्यों पर विचार नहीं किया, जिन्हें जानबूझकर दरकिनार करने की मांग की गई थी, और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII के नियम 3,4 और 5 में आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिवादी द्वारा विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था।

(9) अन्यथा भी, यदि रेलवे कर्मचारियों के लिए 'परिवार पेंशन योजना', 1964 को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियम 75 पर विचार किया जाता है, तो याचिकाकर्ता 'परिवार पेंशन' का हकदार प्रतीत होता है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि मृतक कर्मचारी को 14 साल से अधिक की सेवा में रहने के बावजूद नियमित नहीं किया गया था।सुसंगत नियम 75 (2) में कहा गया है -

“75. रेलवे कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964

(1) .....

(2) उप-नियम (3) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैः-

(क) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद; या

(ख) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले बशर्ते कि संबंधित रेलवे कर्मचारी की सेवा या पद पर नियुक्ति से तुरंत पहले उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकरण द्वारा रेलवे सेवा के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो;

(ग) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद और नियम 53 में निर्दिष्ट पेंशन के अलावा, अध्याय 5 में निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता की प्राप्ति में मृत्यु की तारीख को थाः

मृतक का परिवार पारिवारिक पेंशन 1964 (इसके बाद इस नियम में पारिवारिक पेंशन के रूप में संदर्भित) का हकदार होगा, जिसकी राशि तालिका (मुद्रित नहीं) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

व्याख्याःइस नियम में "निरंतर एक वर्ष की सेवा" पद का अर्थ खंड (ख) में दिए गए "एक वर्ष से कम की निरंतर सेवा" के रूप में लिया जाएगा।

(10) इस प्रकार जो समग्र तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि मृतक कर्मचारी ने 30.07.1992 से लेकर 14.12.2006 पर अपनी मृत्यु तक अपेक्षित एक वर्ष से अधिक सेवा के लिए काम किया था और उसने 5.08.1992 पर आवश्यक चिकित्सा परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी।नतीजतन, नौकरी में उनकी मृत्यु के कारण, उनकी विधवा परिवार पेंशन देने की हकदार बन जाएगी।हालाँकि यह अनुमति नहीं दी गई थी, जाहिरा तौर पर क्योंकि उनकी सेवाओं को 'नियमित नहीं किया गया था'।लेकिन जैसा कि अलका शर्मा भारत का संघ और अन्य संघ के आलोक में तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से विचार करके सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। याचिकाकर्ता के विशिष्ट कथन, और प्रतिवादीओं द्वारा इसे टालने से इनकार, नियमितकरण की इस तरह की कमी के लिए कर्मचारी स्वयं दोषी नहीं था।उन्होंने वर्ष 2000 में आवश्यक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उस उद्देश्य के लिए उत्तरदाताओं के स्वयं के लिखित संचार दिनांक 30.06.2000 के बावजूद उन्हें साक्षात्कार के लिए कभी नहीं बुलाया गया।उन्हें अपने नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से वर्ष 2002 और 2004 द्वारा सफल लिखित परीक्षाओं के बारे द्वारा सूचित भी नहीं किया गया था।वास्तव में, एल. डी. न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी

2000,2001 और 2002 में निर्धारित लिखित परीक्षा को पास नहीं कर सका।यह अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से सही है क्योंकि उन्होंने वास्तव में 2000 में टेस्ट पास किया था, जबकि प्रतिवादीओं की ओर से भी यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई भी टेस्ट 2001 में आयोजित किया गया था।अगले वर्ष 2002 के संबंध में, याचिकाकर्ता का आरोप कि उसके पति को कभी भी परीक्षण देने के लिए सूचित नहीं किया गया था, अभिवचनों में लगभग अप्रमाणित है।इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई नियम या निर्देश रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं कि जब कर्मचारी अपने वरिष्ठों की पूरी संतुष्टि के लिए 14 वर्षों तक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, तो सेवाओं को नियमित करने के लिए "साक्षात्कार" एक अनिवार्य शर्त थी।इसलिए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि काफी हद तक, मृतक कर्मचारी की सेवाओं की जिम्मेदारी उसके जीवनकाल के दौरान अनियमित रहने के कारण, स्वयं प्रतिवादीओं की है।

(11) उपरोक्त कारणों से, न्यायाधिकरण का विवादित आदेश अस्थिर है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।इसलिए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे मृतक कर्मचारी की सेवाओं को नियमित मानते हुए परिवार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अनुदान के लिए आवश्यक कार्य करें।हालाँकि, वह एल. डी. में अपना मूल आवेदन दाखिल करने से पहले केवल तीन साल की अवधि के लिए पेंशन की अवशिष्ट राशि की हकदार होगी। न्यायाधिकरण अर्थात मई, 2012 से आगे।

(12) इस आदेश के संचार की तारीख से चार महीने के भीतर उत्तरदाताओं/अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्य किए जाने चाहिए।

पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा